

संवधान का अनुच्छेद 299: सरकारी अनुबंध

प्रलिस के लयः

संवधान का अनुच्छेद 299, [भारतीय सर्वोच्च नयायालय](#), सरकारी अनुबंध

मेन्स के लयः

सार्वजनिक नधिका सुरक्षा में अनुच्छेद 299 की भूमिका, सरकारी अनुबंधों के संबंध में अनुच्छेद 299 के प्रावधान

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारत के सर्वोच्च नयायालय](#) ने [राष्ट्रपति](#) के नाम पर कयि गए सरकारी अनुबंधों के कानूनी प्रावधानों को स्पष्ट कयि ।

- **गलॉक एशया-पैसफिक लिमिटेड** और केंद्र से संबंधित एक मामले में नयायालय ने फैसला सुनाया कि **भारत के राष्ट्रपति** के नाम पर कयि गए अनुबंध वैधानिक वधिसे प्रतिकषा प्रदान नहीं कर सकते हैं ।
- यह फैसला **संवधान के अनुच्छेद 299** की व्याख्या और सरकारी अनुबंधों के लयि इसके नहितार्थ पर प्रकाश डालता है ।

सरकारी अनुबंध:

- **परचयः**
 - सरकारी अनुबंध सरकार द्वारा **नरिमाण, प्रबंधन, रखरखाव, मरमत्त, जनशक्तिआपूर्ति, आईटी** से संबंधित परयोजनाओं आदि जैसे वभिन्न उद्देश्यों के लयि कयि गए अनुबंध हैं ।
 - सरकारी अनुबंधों में एक **पार्टी के रूप में केंद्र सरकार या राज्य सरकार या एक सरकारी नकियाय और दूसरी पार्टी के रूप में एक नजी वयक्ति या संस्था** शामिल होती है ।
 - सरकारी अनुबंधों को **भारतीय संवधान के अनुच्छेद 299** द्वारा नरिधारित कुछ औपचारकताओं और सुरक्षा नयिमें का अनुपालन करना होता है ।
 - सरकारी अनुबंध **सार्वजनिक जाँच और जवाबदेही के अधीन** हैं और नषिपक्षता, पारदर्शता, प्रतस्पर्धात्मकता एवं गैर-भेदभाव के सिद्धांतों द्वारा शासित हैं ।
- **सरकारी अनुबंधों के लयि आवश्यकताएँ:**
 - अनुबंध को राज्यपाल या राष्ट्रपति द्वारा वयक्त कयि जाना चाहयि ।
 - इसे लिखित रूप में नषिपादित कयि जाना चाहयि ।
 - अनुबंधों का नषिपादन वयक्तियों और [राज्यपाल](#) या [राष्ट्रपति](#) द्वारा नरिदेशित या अधिकृत तरीके से कयि जाना चाहयि ।

संवधान का अनुच्छेद 299:

- **परचयः**
 - संवधान का अनुच्छेद 299 **भारत सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से कयि गए अनुबंधों के प्रकार और स्वरूप से संबंधित** है ।
- **उत्पत्ति:**
 - स्वतंत्रता-पूर्व की अवधि में भी सरकार अनुबंध करती रही ।
 - **1947 के क्राउन प्रोसीडगिस एक्ट** ने अनुच्छेद 299 को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका नषिई ।
 - क्राउन प्रोसीडगिस एक्ट ने नरिदषित कयि कि **क्राउन द्वारा कयि गए अनुबंध के लयि नयायालय में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है** ।
- **उद्देश्य:**
 - अनुच्छेद 299 संघ या राज्य की कार्यकारी शक्ति के प्रयोग में कयि गए अनुबंधों को अभवियक्त और नषिपादित करने के तरीके को दर्शाता

है।

- इसका उद्देश्य सार्वजनिक नधिकी सुरक्षा और अनधिकृत या अवैध अनुबंधों को रोकने के लिये एक विशिष्ट प्रक्रिया स्थापित करना है।

■ अभिव्यक्ति और नषिपादन:

- अनुच्छेद 299 (1) के अनुसार, अनुबंधों को **लिखित रूप में व्यक्त** किया जाना चाहिये और उनकी ओर से राष्ट्रपति या राज्यपाल द्वारा **वधिवित्त अधिकृत व्यक्ति द्वारा** नषिपादित किया जाना चाहिये।

■ राष्ट्रपति/राज्यपाल की प्रतिकक्षा:

- जबकि अनुच्छेद 299 (2) कहता है कि **राष्ट्रपति या राज्यपाल को अनुबंधों के लिये व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है**, यह अनुबंध के कानूनी प्रावधानों से सरकार को प्रतिकक्षा प्रदान नहीं करता है।
 - भारत में सरकार (संघ या राज्यों) पर उसके अधिकारियों द्वारा किये गए अपकृत्यों (नागरिक गलतियों) के लिये मुकदमा चलाया जा सकता है।

सर्वोच्च न्यायालय का नरिणय:

■ मामले की पृष्ठभूमि:

- ग्लोक एशिया-पैसिफिक लिमिटेड (Glock Asia-Pacific Limited) ने नविदा संबंधी विवाद में मध्यस्थ की नयिकृति के संबंध में केंद्र के खिलाफ एक आवेदन दायर किया था।
 - सरकार ने एक नविदा शर्त का हवाला देते हुए दलिली उच्च न्यायालय के एक सेवानवित्त न्यायाधीश की नयिकृति पर आपत्ति जताई थी जिसमें कानून मंत्रालय के एक अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में कार्य करने की आवश्यकता थी।

■ न्यायालय की विचिना:

- सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि मध्यस्थता खंड एक सरकारी अधिकारी को मध्यस्थ के रूप में विवाद को हल करने की अनुमति देता है जो **मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 12 (5)** के साथ वरिधाभासी है।

■ अनुच्छेद 299 की प्रासंगिकता:

- न्यायालय ने इस बात पर ज़ोर दिया कि अनुच्छेद 299 संवदिात्मक दायित्व को शासति करने वाले मौलिक कानूनों का समाधान नहीं करता है बल्कि यह केवल सरकार पर संवदिात्मक दायित्व के साथ बाध्यता की औपचारिकताओं से संबंधित है।

अनुच्छेद 299 से संबंधित अन्य नरिणय:

■ बहिरा राज्य बनाम मजीद (1954):

- सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एक सरकारी अनुबंध को **भारतीय अनुबंध अधिनियम की आवश्यकताओं**, जैसे कि प्रस्ताव, स्वीकृति और विचार के अलावा **अनुच्छेद 299** के प्रावधानों का पालन करना होगा।
- **केंद्र या राज्य सरकार** का संवदिात्मक दायित्व संवदिा के सामान्य कानून के अधीन **किसी भी व्यक्ति के समान है**, जो अनुच्छेद 299 द्वारा वधिति औपचारिकताओं के अधीन है।

■ श्रीमती अलीकुट्टी पॉल बनाम केरल राज्य और अन्य (1995):

- कार्यकारी अभियंता ने एक पुल नरिमाण अनुबंध के लिये एक टेंडर को स्वीकार कर लिया, लेकिन **राज्यपाल के नाम पर हस्ताक्षर नहीं करने के कारण** यह नहीं कहा जा सकता कि अनुबंध **संवधिान के अनुच्छेद 299** के तहत वैध है।
- यह नरिणय संवधिान के अनुच्छेद 299 के औचित्य और दायरे की व्याख्या करता है तथा इस बात पर ज़ोर देता है कि इसके प्रावधान अनधिकृत अनुबंधों के खिलाफ सरकार की सुरक्षा के लिये बनाए गए हैं।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस